

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO-34
ANSWERED ON-06/12/2023

PROMOTION OF NON-POLLUTING FUELS

34. SHRI SANT BALBIR SINGH:

Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

- (a) whether Government has emphasized on the substitution of petrol and development of non-polluting, indigenous methods and alternative fuels (CNG/LNG), to keep the environment clean, if so, the details thereof;
- (b) the steps taken to use CNG, LNG and ethanol for road equipment machinery in the country, specifically for the State of Punjab;
- (c) whether any plan has been prepared to build roadside township, smart city, logistics park, industrial cluster, if so, the details thereof; and
- (d) the details of roads which come under these projects, State-wise?

ANSWER

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(SHRI NITIN JAIRAM GADKARI)

- (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 34 ANSWERED ON 06.12.2023 ASKED BY SHRI SANT BALBIR SINGH REGARDING PROMOTION OF NON-POLLUTING FUELS

(a) To facilitate the development of Motor Vehicles running on non-fossil fuels like CNG, Bio-CNG, LNG, EV, Biofuels, etc. the Ministry of Road Transport & Highways has notified mass emission standards in respect of blends of ethanol with gasoline, flex-fuel, Biodiesel, Bio-CNG, Liquefied Natural Gas (LNG), blends of Methanol with gasoline, dual fuel, Hydrogen etc.

Further, the Production Linked Incentive (PLI) scheme for Automobile & Auto Components incentivizes the Auto OEMs (Original Equipment Manufacturers) to accelerate the introduction of Flex Fuel vehicles in India.

(b) The Government vide GSR 1151(E) dated 29th November, 2018 had already notified norms for dual fuel use of CNG/Bio-CNG/LNG in Agricultural tractors, power tillers, Combined Harvestors and Construction Equipment Vehicles (CEV).

(c) and (d) Gati Shakti National master Plan provides for the overall framework for the creation of a system for interconnected and multimodal infrastructure projects. Accordingly, concerned Ministries/Departments undertake projects taking into account available and planned infrastructure. Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA), Government of India have approved development of 35 Multi Modal Logistics Parks (MMLPs).to be undertaken by Ministry of Road Transport & Highways. The perspective of development of MMLPs is location-wise and not on road-wise. The list of approved locations is as under:-

Sr. No.	Locations	State
1	Delhi-NCR (Delhi, Gurgaon, Ghaziabad, Faridabad, Noida)	Delhi/Haryana/UP
2	Mumbai (Mumbai, Mumbai Suburbs, JNPT, Mumbai Port, Raigad District)	Maharashtra
3	North Gujarat (Ahmedabad and Vadodara)	Gujarat
4	Hyderabad	Telangana
5	South Gujarat (Surat and Bharuch)	Gujarat
6	South Punjab (Ludhiana, Sangrur, Patiala)	Punjab
7	North Punjab (Amritsar, Jalandhar, Gurudaspur)	Punjab
8	Jaipur	Rajasthan
9	Bangalore	Karnataka
10	Pune	Maharashtra
11	Vijayawada	Andhra Pradesh
12	Chennai	Tamil Nadu
13	Nagpur	Maharashtra
14	Indore	Madhya Pradesh
15	Patna	Bihar
16	Kolkata	West Bengal
17	Ambala	Haryana
18	Valsad	Gujarat
19	Coimbatore	Tamil Nadu
20	Jagatsinghpur	Odisha
21	Nasik	Maharashtra
22	Guwahati	Assam
23	Kota	Rajasthan

24	Panaji	Goa
25	Hisar	Haryana
26	Visakhapatnam	Andhra Pradesh
27	Bhopal	Madhya Pradesh
28	Sundargarh	Odisha
29	Bhatinda	Punjab
30	Solan	Himachal Pradesh
31	Rajkot	Gujarat
32	Raipur	Chhattisgarh
33	Jammu	UT of Jammu
34	Kandla	Gujrat
35	Cochin	Kerala

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *34

जिसका उत्तर 06.12.2023 को दिया जाना है
गैर-प्रदूषणकारी ईंधन को बढ़ावा देना

*34. श्री संत बलबीर सिंह:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेट्रोल के प्रतिस्थापन और गैर-प्रदूषणकारी, स्वदेशी तरीकों और वैकल्पिक ईंधन (सीएनजी/एलएनजी) के विकास पर जोर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में, विशेष रूप से पंजाब राज्य के लिए, सड़क उपकरण मशीनरी के लिए सीएनजी, एलएनजी और इथेनॉल का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सड़कों के किनारे बस्तियां, स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की कोई योजना तैयार की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाली सड़कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

गैर-प्रदूषणकारी ईंधन को बढ़ावा देने के संबंध में श्री संत बलवीर सिंह द्वारा पूछे गए दिनांक 06.12.2023 को राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 34 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण का उत्तर

(क) सीएनजी, बायो सीएनजी, एलएनजी, ईवी, जैव-ईंधनों इत्यादि जैसे गैर जीवाश्म ईंधन पर चलने वाले मोटर वाहनों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गैसोलीन के साथ इथेनॉल के मिश्रण, फ्लेक्स-फ्यूल, बायोडीजल, बायो-सीएनजी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), गैसोलीन के साथ मेथनॉल का मिश्रण, दोहरा ईंधन, हाइड्रोजन इत्यादि के संबंध में बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है।

इसके अलावा, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना भारत में फ्लेक्स फ्यूल वाहनों की शुरुआत में तेजी लाने के लिए ऑटो ओईएम (मूल उपकरण निर्माताओं) को प्रोत्साहित करती है।

(ख) सरकार ने सा.का.नि 1151(अ) दिनांकित 29 नवंबर 2018 के माध्यम से कृषि ट्रैक्टरों, पॉवर टिलर्स, कंबाइंड हार्वेस्टर्स और निर्माण उपकरण वाहनों (सीईवी) में सीएनजी/बायोसीएनजी/एलएनजी के दोहरे ईंधन उपयोग के लिए मानकों को पहले ही अधिसूचित कर दिया था।

(ग) और (घ) गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इंटरकनेक्टेड और मल्टीमॉडल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए एक प्रणाली के निर्माण के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करता है। तदनुसार, संबंधित मंत्रालय/विभाग मौजूदा और नियोजित अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं को शुरू करता है। भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) बनाए जाने का अनुमोदन किया है, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाएगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के विकास का स्वरूप स्थान-वार है, न कि सड़क-वार।

अनुमोदित स्थानों की सूची की सूची निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	स्थान	राज्य
1	दिल्ली-एनसीआर (दिल्ली, गुडगांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा)	दिल्ली/हरियाणा/यूपी
2	मुंबई (मुंबई, मुंबई उपनगर, जेएनपीटी, मुंबई पोर्ट)	महाराष्ट्र
3	रायगढ़ जिला	गुजरात
4	उत्तर गुजरात (अहमदाबाद और वडोदरा)	तेलंगाना
5	हैदराबाद	गुजरात
6	दक्षिण गुजरात (सूरत और भरुच)	पंजाब
7	दक्षिण पंजाब (लुधियाना,संगरूर,पटियाला)	पंजाब
8	जयपुर	राजस्थान
9	बैंगलोर	कर्नाटक
10	पुणे	महाराष्ट्र
11	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
12	चेन्नई	तमिलनाडु
13	नागपुर	महाराष्ट्र
14	इंदौर	मध्य प्रदेश
15	पटना	बिहार
16	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
17	अंबाला	हरियाणा
18	वलसाड	गुजरात
19	कोयंबटूर	तमिलनाडु
20	जगतसिंहपुर	ओडिशा
21	नासिक	महाराष्ट्र

22	गुवाहाटी	असम
23	कोटा	राजस्थान
24	पणजी	गोवा
25	हिसार	हरियाणा
26	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
27	भोपाल	मध्य प्रदेश
28	सुंदरगढ	ओडिशा
29	भटिंडा	पंजाब
30	सोलान	हिमाचल प्रदेश
31	राजकोट	गुजरात
32	रायपुर	छत्तीसगढ
33	जम्मू	संघ शासित क्षेत्र जम्मू
34	कांडला	गुजरात
35	कोचीन	केरल

श्री संत बलबीर सिंह : * "चेयरमैन साहब, आपने समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मंत्री जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से पर्यावरण के विषय में बात करना चाहता हूँ। आज सबसे अधिक प्रदूषण डीज़ल से चलने वाले वाहनों के कारण फैल रहा है। आज लुधियाना सबसे अधिक प्रदूषित शहर है और इसका प्रमुख कारण डीज़ल से चलने वाले वाहन हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए क्या सरकार पेट्रोल की जगह कोई वैकल्पिक प्रदूषण रहित ईंधन के विकास पर काम कर रही है? यदि हाँ, तो कृपया उसका विवरण प्रस्तुत करें। देश में और विशेष कर पंजाब में सड़कों के निर्माण के लिए जिस मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें डीज़ल के स्थान पर सी.एन.जी, एल.एन.जी, इथेनॉल इत्यादि वैकल्पिक ईंधनों के प्रयोग के बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है, कृपया उसके विषय में बताया जाए।"

श्री नितिन जयराम गडकरी : माननीय सभापति महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में जो 40 per cent emission of CO2 है, pollution है, वह transport sector में होता है और यह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यह चिन्ता का विषय है। There is 330 million metric tonnes of CO2 emission every year. It is a very dangerous problem. इसमें से हमारे देश में जो 85 per cent fuel है, वह fossil fuel है, जो कि import होता है, जिसके import की cost 16 लाख करोड़ रुपये है। इकोनॉमी और पॉल्यूशन, दोनों के हिसाब से यह बहुत गंभीर समस्या है। विशेष रूप से, पेट्रोल और डीज़ल के कारण जो पॉल्यूशन होता है, जिसकी बात सम्माननीय सदस्य ने रखी है, उसके लिए भारत सरकार ने काफी प्रयास किए हैं और उसे प्रायोरिटी दी है। सभापति महोदय, इंडिया कार मैनुफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग में पहले पाँचवें नंबर पर था, पर आज हमारा नंबर तीसरा हो गया है। इसमें पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है और फिर हम हैं। हमने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। एक बात यह भी है कि इसका ग्रोथ रेट बहुत बढ़ा है। टोटल व्हीकल्स में यह 9.91 परसेंट है और कार एवं फोर व्हीलर्स में 20 परसेंट है। यह इंडस्ट्री भारत सरकार और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी दे रही है और इसमें साढ़े चार करोड़ जॉब्स क्रिएट हुई हैं। इसके बावजूद, सम्माननीय सदस्य ने जो बात रखी, उसके आधार पर भारत सरकार ने ऑल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल, इन दोनों को विशेष रूप से प्राधान्य दिया है। यह जो जी20 समिट हुआ था, उसमें ग्लोबल बायोफ्यूल एलायंस निश्चित किया गया और यह टारगेट तय किया गया कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशन तक जाएंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने ऑल्टरनेटिव फ्यूल पर अलग प्रकार के प्रयोग किए हैं। सर, मैं खुद इसका बाहर प्रचार करता रहता हूँ। मैं पार्लियामेंट में आता हूँ, तो हाइड्रोजन की गाड़ी में आता हूँ और अभी मैं फ्लैक्स इंजन की गाड़ी में आता हूँ। ये दोनों भी गाड़ियाँ हैं। फ्लैक्स इंजन का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो ब्रोकर राइस, बायोमास, शुगरकेन जूस और मोलेसेस हैं, इनसे इथेनॉल बनता है और टोयोटा की इनोवा गाड़ी 100 परसेंट इथेनॉल पर चलती है। अभी बाकी कंपनीज भी ऐसी गाड़ी लॉन्च कर रही हैं, जो 100 परसेंट इथेनॉल पर चलेगी। सर, इथेनॉल का रेट है, 60 रुपये लीटर और पेट्रोल का रेट है, 120 रुपये लीटर। इसके साथ ही, यह इथेनॉल की गाड़ी 60 परसेंट

* Hindi translation of the original speech delivered in Punjabi.

बिजली तैयार करती है, तो इससे भी पॉल्यूशन कम होता है। हमने पहले फ्लैक्स इंजन को प्रोत्साहन दिया। ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स तो फ्लैक्स इंजन ला रहे हैं, पर बजाज, टीवीएस और हीरो अपनी मोटरसाइकिल भी लेकर आए हैं। हम पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ मिलकर जल्दी ही इथेनॉल पम्प की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे इस प्रॉब्लम के बड़े प्रमाण पर कम होने में मदद मिलेगी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि all types of excess foodgrains और excess sugar - इससे किसानों की स्थिति सुधर जाएगी। It is diversification of agriculture towards energy and power sector. इस साल गन्ना किसानों को जो भाव मिले हैं, उसके कारण हम इथेनॉल की इंडस्ट्री और इथेनॉल को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे देश में छः लाख मोबाइल टावर्स हैं और उनके ऊपर डीजल जेनरेटर्स हैं। यह जो छः लाख मोबाइल टावर्स हैं, इनमें से एक को 8,000 लीटर डीजल लगता है। आज केवल ये जेनरेटर्स ही 250 करोड़ लीटर डीजल यूज कर रहे हैं। हम लोग इसे कम करने के लिए इथेनॉल बेस्ड लाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में जो स्प्रेयिंग होती है, वह ड्रोन lithium-ion बैटरी पर चलता है। उसे भी फ्लैक्स इंजन पर लाने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा, मैं आदरणीय सदस्यों को यह विशेष रूप से कहूँगा कि हमने बायोमास से, पराली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी को बहुत प्रोत्साहन दिया है। इसके कारण शुगर मिल वेस्ट, जैसे प्रेस मड, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और पराली है, इसके कम-से-कम 36 प्लांट्स चालू हो गए हैं, जो सीएनजी बना रहे हैं। इसके साथ ही, इसके 175 प्लांट्स प्रोसेस में हैं और मैक्सिमम पंजाब में बन रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पानीपत में इंडियन ऑइल ने पराली से इथेनॉल बनाने का अपना पहला प्लांट डाला है, जो एक लाख लीटर इथेनॉल तैयार करता है और 150 टन bio-bitumen तैयार करता है, जो कि रोड्स में काम में आता है। हमें 80 लाख टन bitumen लगता है, जिसमें से 30 लाख टन हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। यह पराली जलाने से जो प्रदूषण होता है, अब इसकी बजाय bio-bitumen बनेगा वहीं अब बायो एविएशन फ्यूल बन रहा है। जो हवाई ईंधन है, उसमें भी वर्ल्ड लेवल पर एक परसेंट डालने का प्रोविज़न हुआ है और यह ईंधन भी देश में बनेगा। मुझे विश्वास है कि यह ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का फ्यूल है।

सम्माननीय सभापति महोदय, मैं हाइड्रोजन की कार में ही काफी बार आता हूँ। सरकार ने हाइड्रोजन तैयार करने के लिए अभी पाँच हाइड्रोजन मिशंस बनाए, जिनमें हमको 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन प्रति वर्ष लगेगा। हाइड्रोजन तीन प्रकार का है। जो कोयले से बनता है, वह ब्लैक हाइड्रोजन है, जो पेट्रोलियम से बनता है, वह ब्राउन हाइड्रोजन है और जो पानी, बायोमास या म्युनिसिपल वेस्ट्स से बनता है, वह ग्रीन हाइड्रोजन है। सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया है। Knowledge to wealth and waste to wealth. जैसे, innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices को हम नॉलेज कहते हैं, उसी तरह, इस टेक्नोलॉजी को लाकर हम knowledge to wealth और no material is waste; no person is waste की ओर बढ़ रहे हैं। It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. सर, हमने हाइड्रोजन तैयार करने के लिए यह उपक्रम भी अपने हाथ में लिया है। इससे बहुत बड़ा रोजगार निर्मित होगा और किसानों को भी फायदा होगा। अभी इसका रेट 300 रुपये प्रति किलोग्राम है, क्योंकि यह electrolyzer से बनता है, जिसमें 50 यूनिट पावर

लगती है। हमारे यहाँ, विशेष रूप से बेंगलुरु का Indian Institute of Science और मुम्बई में यादव नाम से एक केमिकल इंस्टिट्यूट है, जिन्होंने बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन बनाया है। हमारा यह प्रयास है कि इसका रेट एक डॉलर से भी कम आए। अगर यह एक डॉलर से भी कम में आएगा और एग्रीकल्चर बायोमास का उपयोग होगा तो किसान समृद्ध और संपन्न होगा। हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, बल्कि ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनें, प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी यही महत्वाकांक्षा है। इसीलिए विशेष रूप से जी20 में जो ग्लोबल एलायंस हुआ, वह इसी के लिए एक प्रयास है।

सर, माननीय सदस्य ने एक बात construction equipments के बारे में भी कही कि वे भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं। मैंने दो दिन पहले हाइड्रोजन पर चलने वाला JCB लॉन्च किया है और अब जल्द ही कंस्ट्रक्शन ट्रक्स और बसेज में हाइड्रोजन आएगा। अब ऑल्टरनेटिव फ्यूल के रूप में तो इलेक्ट्रिक पॉपुलर हो गया और electric scooters, electric cars, electric bus आदि भी कॉमन हो गए। अब धीरे-धीरे ऑल्टरनेटिव फ्यूल तथा बायोफ्यूल का उपयोग करके तथा वेस्ट्स से एनर्जी तैयार करके हम किसानों की भी आर्थिक स्थिति सुधारे और प्रदूषण को कम करें, ऐसी कोशिश सरकार की ओर से हो रही है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary; Shri Sant Balbir Singh.

श्री संत बलबीर सिंह : "बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सड़कों के किनारे स्मार्ट सिटी, टाउनशिप, लॉजिस्टिक पार्क एवं उद्योग क्लस्टर बनाने की कोई योजना तैयार की गई है? यदि हाँ, तो उसका विवरण दें। किन-किन सड़कों पर ये परियोजनाएं शुरू की जाएंगी, उनका राज्यवार ब्योरा दिया जाए।"

श्री नितिन जयराम गडकरी: सम्माननीय सभापति महोदय, हम देश में टोटल 35 multi modal logistic parks (MMLP) बना रहे हैं। इसमें असम के जोगीघोपा में जो MMLP है, वह मल्टीमॉडल है। यानी, उसमें रोड भी है, हवाई जहाज के लिए एयरपोर्ट भी है, जलमार्ग भी है और उनके साथ रेलवे भी है। आदरणीय सदस्य पंजाब से आते हैं, वहाँ भी नॉर्थ पंजाब में अमृतसर, जालंधर और गुरदासपुर में pre-feasibility study कम्प्लीट हुई है, जिसका हम विचार कर रहे हैं। साउथ पंजाब में लुधियाना, संगरूर और पटियाला में हम लोग लैंड के लिए स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। इसके अलावा, हम लोग बठिंडा में भी काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमने बठिंडा से जामनगर रिफाइनरी के लिए करीब 28,000 करोड़ रुपये खर्च करके एक बहुत बड़ा डायरेक्ट एक्सप्रेस हाईवे बनाया है। उसके आजू-बाजू भी हम इस प्रकार की बातें सोच रहे हैं। हम विशेष रूप से 670 road side amenities बना रहे हैं, जिनमें से पंजाब में 40 हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि पंजाब में उन 40 में से 7 के लिए वर्क अवॉर्ड हुआ है और 33 under bidding हैं। देश में ऐसी टोटल 640 road side amenities होंगी। हम वहाँ पर वहीं के फूड्स और वहीं के हैंडलूम्स-हैंडिक्राफ्ट्स का भी प्रोत्साहन करेंगे। वहाँ पर पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी,

* Hindi translation of the original speech delivered in Punjabi.

एलएनजी, एथेनॉल के पम्प भी होंगे और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी होंगे। विशेष रूप से, चूंकि वहाँ पर लोग रुक सकते हैं, इसलिए वहाँ पर उनके एंटरटेनमेंट की भी व्यवस्था होगी। इस प्रकार, इन दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन करने की कोशिश हो रही है।

श्रीमती रंजीत रंजन : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि हम प्रदूषण को कम करने की बात कर रहे हैं, वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए हम इलेक्ट्रिक वाहन को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन क्या यह बात सही है कि एक रिसर्च आया है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं, बैटरीज़ हैं, वे जिस प्रोसेस से बनती हैं, उसमें बनाने वालों की सेहत को ज्यादा खतरा है और जब बैटरी लाइफ खत्म होती है तो उसको डम्प करने का जो प्रावधान है, उससे हमारी धरती और भी ज़हरीली होगी, फर्टाइल लैंड को नुकसान होगा? क्या प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करना डीज़ल और पेट्रोल से बेहतर है या उससे भी ज्यादा खतरनाक है? जो रिसर्च है, वह यह कहता है कि यह उससे भी ज्यादा खतरनाक है।

श्री नितिन जयराम गडकरी : आदरणीय सभापति महोदय, हमारे देश में 16 लाख करोड़ रुपये का fossil fuel का इम्पोर्ट होता है, उसका प्रदूषण कितने बड़े पैमाने पर है, यह दिल्ली वालों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक लीथियम आयन बैटरी है, उस बैटरी में चार chemistry हैं, एक एल्युमिनियम, एक लीथियम के साथ जिंक, एल्युमिनियम, स्टील आयन बैटरी है, इसकी केमिस्ट्री पर भी काम हो रहा है। एक एल्युमिनियम एयर टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है।

महोदय, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पेट्रोल और डीज़ल के लिए हम 110-120 रुपये लगाते हैं, वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमारे 10 रुपये लगते हैं। हम हमारे टिकट रेट्स कम कर सकेंगे। लीथियम आयन बैटरी की कॉस्ट 150 dollar per unit की थी, किंतु अब वह 115 dollar पर आयी है। जो per kilowatt 150 डॉलर की थी, अब वह 115 पर आयी है। अब हमारे देश में भी लीथियम आयन मिला है। जम्मू-कश्मीर में विश्व का छठा largest lithium-ion reserve मिला है। हम 1,200 टन लीथियम आयन import करते हैं। मुझे विश्वास है कि अभी तक इस प्रकार के रिसर्च की जो बात कर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। अगर आएगी तो हम इसके ऊपर अवश्य विचार करेंगे। हमारी वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात कही थी, जिसमें हम लोग वेस्ट मैटीरियल की सर्कुलेशन इकोनॉमी बनाएं। अभी हमारे पास कार की स्क्रेपिंग हो रही है, रबर टायर की स्क्रेपिंग करके जो रबर निकलता है, उसे बिटुमेन में डालने का काम 15 परसेंट कर रहे हैं। प्लास्टिक का 7 परसेंट रोड में डाल रहे हैं, उसी प्रकार से iron slag का उपयोग कर रहे हैं। हमने तो केवल इकोलॉजिकल एन्वायनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिल्ली का म्युनिसिपल वेस्ट 25 लाख टन, अहमदाबाद का 25 लाख टन और दिल्ली मुम्बई हाईवे में और डाला। ऐसा 50 लाख टन म्युनिसिपल वेस्ट रोड के अंदर डाल दिया। जहां तक आपने लीथियम आयन बैटरी की बात की है, इसके बारे में हम पूरी चिंता करेंगे और इसकी रीसाइक्लिंग करने में कहीं भी उसके दुष्परिणाम न आएँ, कहीं भी कोई नई समस्या न हो, इसकी चिंता सरकार करेगी। यह केमिस्ट्री रोज़ बदल रही है, यह फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। Our Government is working in that direction with futuristic technology, futuristic vision and

futuristic planning. 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने का प्रधान मंत्री जी का जो सपना है, वर्ल्ड की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाने का जो सपना है, मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि आने वाले 5 साल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बसेज़, even ट्रक्स भी, इनको एक्सपोर्ट करने वाला पहले नम्बर का देश हिन्दुस्तान बनेगा। इतना पोटेंशियल हमारे पास है और इतना काम हो रहा है। वर्ल्ड के सब reputed brands हैं, साढ़े बारह लाख करोड़ रुपये की इकोनॉमी है। अब जापान को पीछे छोड़कर हम तीसरे नम्बर पर आए हैं और निश्चित रूप से जल्द ही हम और आगे जाएंगे। इसमें बहुत अच्छी तरह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नए रोज़गार पैदा होंगे और देश समृद्ध होगा, निश्चित रूप से मुझे यह विश्वास है। अगर ऐसी कोई बात होगी या रिपोर्ट आएगी, तो सरकार की ओर से उस पर निश्चित रूप से चिंता की जाएगी।

SHRI KARTIKEYA SHARMA: Sir, I would like to know from the hon. Minister about the status of adoption of e-vehicles and the steps taken for their promotion in the State of Haryana and NCR Region.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: The subject is related with the Heavy Industries Ministry and the Urban Development Ministry. I think you are talking about purchasing of e-buses...

SHRI KARTIKEYA SHARMA: E-vehicles.

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: For e-vehicles, there is no problem. In the Government everywhere and even in the private sector, people are using e-vehicles. It is very popular. The only problem is the cost difference between petrol/diesel vehicles and e-vehicles. Cost of e-vehicles is high. It is dependent upon volume. When volume increases, I feel -- it is my estimate; I am not giving you a promise-- that within one-and-a-half years, the cost of petrol/diesel vehicles and the cost of electric vehicles will be the same. Suppose the expenditure on petrol four-wheeler vehicle is Rs.30,000 per month; for electric, it will come down to Rs.3,000 or Rs.4,000 per month. So, there is a saving and no pollution.

DR. FAUZIA KHAN: Mr. Chairman, Sir, while I must acknowledge it because hon. Minister is from Maharashtra and his work and his vision must definitely be admired, but, through you, I would like to ask the hon. Minister one point. Many times, he has visited the place where we live. He himself will say that the condition of the highways and HAM roads there is very, very poor because of the poor quality of construction. When the road is actually constructed, MoRTH guidelines are not followed. One example is, for embankment level, the particle size has to be 75 mm; in sub-grade, it

has to be 50 mm. It cannot be more than that. But we see that huge boulders are put on roads and nobody is supervising it. Because of that, roads break very, very soon. Sir, it is a very important issue.

MR. CHAIRMAN: Your question please!

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I am sure the Minister will agree with me. It is because of this and because of lack of supervision. External consultants are hired and actual officers are not supervising.

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, please ask your supplementary question.

DR. FAUZIA KHAN: I just want to ask one thing from the Minister. If MoRTH guidelines are not followed, what is the accountability of the officers? What punishment is prescribed?

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: Mr. Chairman, Sir, the question which the hon. Member is asking is not related to this question.

श्री सभापति : यह सीधे महाराष्ट्र का मामला है।

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: I know that she is complaining for that particular road in Parbhani District for many days. We have checked all quality norms and I am very much cautious about it and we are transparent, time-bound, result-oriented and corruption-free. Up till now, for the last 10 years, we have awarded works of more than Rs.50 lakh crores with Government Budget and public-private investment. Our quality is well-known to the people but still if the hon. Member is complaining about the quality of a road in Maharashtra, we will check it up. Many Members from Maharashtra are present here. We are spending Rs.5 lakh crore on road construction in Maharashtra. Still, I will again check up the particular case of quality issue of that road, of which the hon. Member has given me the reference. I will see how it can be improved further.

MR. CHAIRMAN: Question No. 35.